Subject:- History Hons
D II - Paper - IV
Unit - III
Lecture - 24

Dr. Hem Narayan Mahto
R.N. College, Pandaul
9835007357

Date - 21. 4. 2020

Ques:- मलाया में स्वाधीनता संघर्ष पर प्रकाश डालिए।

Ans:- मलाया स्याम की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में है। सिंगापुर को छोड़कर सम्पूर्ण मलाया प्रायद्वीप में 11 छोटे राज्य हैं और इसका कुल क्षेत्रफल तिरपन हजार वर्गमील है। 1940 ई० में इसकी जनसंख्या 50 लाख के लगभग थी। इस प्रायद्वीप के मध्य में पर्वतमालाएँ हैं जो चार हजार से आठ हजार फुट ऊँची है। नीचे तराई का मैदान है और शेष क्षेत्र समुद्र-तटीय मैदान है, जो कहीं-कहीं तो बहुत चौड़ा है और कहीं-कहीं संकरा। पश्चिमी तट के इसी मैदानी क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र में रबर पैदा होता है।

यूरोपीयों का आगमन:- इस प्रदेश में 16वीं सदी के प्रारम्भ में सर्वप्रथम पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ। 1511 ई० में उन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। पुर्तगाली नियंत्रण में मलक्का शीघ्र ही पूर्व में पुर्तगाल के व्यापार की मण्डी बन गया, जहाँ जायफल, काली मिर्च, कपूर, रेशम और लौंग का व्यापार होता रहा और एक शताब्दी तक पुर्तगाल पूर्व के व्यापार का स्वामी बना रहा। 17वीं शताब्दी में हालैंड के लोग इस क्षेत्र में अपने व्यापार का विस्तार करने में प्रवृत्त हुए और 1641 ई० में मलक्का पर उन्होंने अपना अधिकार कायम कर लिया। फ्रांस की राज्यक्रांति तक मलक्का इन्हीं के हाथ में ही रहा।

अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और सितम्बर 1945 में ब्रिटिश सेनाओं ने मलाया में प्रवेश किया और तब इन्होंने पाया कि देश के भीतर

Scanned with CamScanner

एक ऐसी राष्ट्रीयता का जन्म हो चुका था जो पहले वहाँ नहीं थी। इस स्थिति में मलाया में पहले की तरह शासन करना अब सम्भव नहीं था। अक्टूबर 1945 ई० में ब्रिटिश शासन ने सभी मलय राज्य तथा पेनांग की खाड़ी एवं मलक्का को मिलाकर मलाया संघ बनाने का प्रस्ताव किया। यह तय हुआ कि मलाया संघ ~~सरकार~~ का एक गवर्नर हो जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा हो तथा संघ के शासन नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी भी उसी की हो। इस प्रस्ताव में संघ के लिए एक विधानसभा के निर्माण की बात भी थी। आरम्भिक कदम के रूप में मलाया के विभिन्न सुल्तानों से अपनी सत्ता ब्रिटिश सरकार को सौंपने के लिए कहा गया। लेकिन इस योजना में तीनों जातियों - मलय, चीनी और भारतीय - को नागरिकता का बराबर अधिकार दिया गया।

मलय राष्ट्रवादियों ने इसका उक्त योजना का विरोध किया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति में संशोधन करना पड़ा। युनाइटेड मलाया नेशनल आर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक नई योजना (फरवरी 1948) तैयार की गई। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी :-

(1) मलाया के दसों राज्यों की पृथक सत्ता कायम रखी गई।

(2) इन सभी राज्यों को मिलाकर एक मलाया संघ बनाया गया। संघ की पृथक सरकार और विधान परिषद कायम की गई।

(3) मलाया के शासन की देखभाल के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से एक हाई कमिश्नर को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई।

(4) राज्यों के सुल्तानों को वे सभी अधिकार दे दिए गए जो जापानी आक्रमण से पूर्व उन्हें प्राप्त थे।

Scanned with CamScanner

(5) रक्षा और विदेशी मामलों पर पूरा नियन्त्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों रहा। स्थायी रूप से आकर बसनेवालों को पन्द्रह वर्ष के निवास के बाद नागरिकता देने की व्यवस्था की गई।
(6) इस योजना में सिंगापुर को शामिल नहीं किया गया।

साम्यवादियों का विद्रोह :- 1948 ई० की योजना को कार्यान्वित करके मलाया में एक नई सरकार की स्थापना हो गई। लेकिन इसके साथ ही मलाया में साम्यवादियों के नेतृत्व में उग्र और सशस्त्र विद्रोह भड़क उठा। मलाया में साम्यवादी आन्दोलन 1939 ई० में ही शुरू हो गया था। जब यूरोप में युद्ध प्रारम्भ हुआ था, उस समय मलाया में चीनी साम्यवादियों ने सिंगापुर के जहाजी कर्मचारियों में अशान्ति उत्पन्न कर ब्रिटिश सरकार के लिए परेशानी पैदा कर दी थी। मलाया में जापानियों का अधिकार होने पर साम्यवादियों ने गुप्त जापान विरोधी प्रतिरोध का संचालन किया। जापान के विरुद्ध संघर्ष में अत्यधिक तत्परता प्रदर्शित करने के कारण मलाया में कम्युनिस्टों की शक्ति बहुत बढ़ गई।

युद्ध के बाद मजदूर संगठनों पर उनका पूरा प्रभाव कायम हो गया था। मलाया के सम्बन्ध में अंग्रेजों की विविध योजनाओं को नामंजूर करने में मलाया के कम्युनिस्ट सबसे आगे थे। वे सुलतानों के शासन तथा ब्रिटिश आधिपत्य की मांग कर रहे थे। 1948 ई० से उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। कम्युनिस्टों को अपने लिए सैनिक और रसद उन चीनियों से मिली थी, जो लाखों की संख्या में जापानी अधिकार की अवधि में शहरों को छोड़कर गाँवों को चले गये थे। इन अड्डों से साम्यवादियों ने अपनी मलय

राष्ट्रीय मुक्ति सेना का संगठन किया। इस सेना का उद्देश्य स्वतन्त्र मलय जनवादी लोकतन्त्री गणतन्त्र कायम करना था। जिसमें सभी जातियों का बराबरी के अधिकार मिलते। मलाया में कुओमिनतांग के समर्थकों, बगान मालिकों, सरकारी अधिकारियों तथा व्यापारियों की हत्या साधारण बात हो गई।

1949 ई० में चीन में साम्यवादी व्यवस्था के कायम होने से मलाया के साम्यवादियों का उत्साह पहले की अपेक्षा और भी बढ़ गया। ब्रिटेन ने कम्युनिस्टों के विद्रोह दबाने के उग्र उपायों का अवलम्बन किया। यह संघर्ष 1948 ई० से 1955 ई० तक चलता रहा और इसी कारण 1948 ई० की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। ब्रिटिश सरकार ने मलाया के कम्युनिस्ट विद्रोह को दबाने का अथक प्रयत्न किया। सम्पूर्ण देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई और व्यापक पैमाने पर उनके विरुद्ध प्रतिशोधात्मक कार्यवाही की गई। अन्तत: सरकारी सेनाओं के दबाव के कारण साम्यवादी छापामार सेनाओं को घने जंगलों में शरण लेनी पड़ी। साम्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान पर पचास करोड़ पौण्ड से भी अधिक धनराशि खर्च की गई तो असंख्य लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, फिर भी कम्युनिस्टों के संघर्ष में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने जंगलों में छिपकर युद्ध जारी रखा। 1955 ई० तक साम्यवादी छापामारों की शक्ति बिल्कुल नष्ट तो नहीं हुई, परन्तु उनमें बहुत कमी आ गई। अतएव 1948 ई० की योजना को अब कार्यान्वित किया जा सकता था।

Scanned with CamScanner

स्वतंत्र मलाया का निर्माण :- 1955 ई० में मलाया की संघीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। इसमें अधिकांश वे ही लोग चुने गए जो अपने देश के लिए पूर्ण एवं अविलम्ब स्वतन्त्रता के समर्थक थे। अब ब्रिटेन के लिए यह सम्भव नहीं रहा कि वह मलाया की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा कर सके। जनवरी 1956 ई० में मलाया की राजनीतिक नेताओं का एक शिष्टमंडल लन्दन गया। इनका उद्देश्य ब्रिटिश नेताओं से बातचीत करके एक ऐसी योजना का निर्माण करना था जिसके अन्तर्गत मलाया को पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। दोनों पक्षों के मध्य बातचीत के उपरान्त मलाया की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित समस्याओं की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया गया। जून 1956 में इस आयोग ने अपना कार्य प्रारम्भ किया और कुछ दिनों के बाद एक लम्बा-चौड़ा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। इसी प्रतिवेदन के आधार पर मलाया को पूर्ण स्वतन्त्र करने की योजना बनी।

31 अगस्त 1957 को ब्रिटेन ने मलाया पर से अपना प्रभुत्व समाप्त कर लिया और मलाया ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली। इस योजना के अनुसार मलाया के राज्यों का एक नया संघ बनाया गया। इस संघ में कुल दस राज्य सम्मिलित हुए - नौ वे राज्य जिन पर सुलतानों का शासन था तथा दसवीं इकाई सिंगापुर को छोड़कर स्टेट्स सेटलमेन्ट्स था। सम्पूर्ण मलाया के राजा के पद वह वहाँ के नौ सुलतान

अपने में से किसी एक को पाँच वर्षों के लिए निर्वाचित करते हैं। लेकिन देश का वास्तविक शासन एक मंत्रिपरिषद के हाथ में है जो जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा में दो सदन रखे गये। इस योजना के अनुरूप 31 अगस्त 1958 को मलाया को स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई। इस नवीन राज्य ने तत्काल ही संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी प्राप्त की।

मलाया को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई थी, परन्तु जिस प्रकार मलाया को एक संघ में केन्द्रित कर स्वतन्त्रता दी गई थी उसमें सिंगापुर को अलग कर दिया गया। अतः अब सिंगापुर में स्वतन्त्रता के लिए आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश सरकार जो कि सिंगापुर को अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहती थी, अन्ततः राष्ट्रवादियों के सम्मुख झुकना पड़ा और 1959 में सिंगापुर को स्वतन्त्र करना पड़ा।

Dr. Hem Narayan Mahto
Associate Professor
Deptt. of History
R.N. College, Pandaul
Madhubani